

FII का भारत के सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड्स में नविश

प्रलिम्स के लिये:

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI), विदेशी संस्थागत नविशक, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, वैधानिक तरलता अनुपात, नियंतरक और महालेखा परीकृषक

मेन्स के लिये:

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड, ग्रीन बॉण्ड की स्थिति, ग्रीन फाइनेंस पहल

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrBs) भारत की निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था के लिये वित्तपोषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं, इसके लिये हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) के अंर्तगत कार्य करने वाले विदेशी संस्थागत निशकों (FII) को निवेश करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है जो इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

नोट:

- FII संस्थागत नविशक हैं जो अपने संगठन के स्थान से भिनन देश की परिसंपततियों में नविश करते हैं।
- भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (SEBI) देश में FII निवश को नियंत्रित करता है, जबकि RBI, FII भागीदारी को नियंत्रण में रखने के लिये निवश सीमा को बनाए रखता है।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड (SGrBs) क्या हैं?

- परचियः
 - केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने SGrBs जारी करने की घोषणा की, यह एक प्रकार का सरकारी ऋण है जिससे विशेष रूप से नयून कार्बन अर्थव्यवस्था में भारत की परियोजनाओं को वित्रपोषित किया जाता है।
 - SGrBs के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि विशेष रूप से हरित परियोजनाओं के लिये निर्धारित की जाती है, जिससे फंड के उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
 - SGrBs आमतौर पर सरकारी-परतिभूतियों (G-Secs) की तुलना में कम ब्याज दरों को प्रस्तुत करते हैं, जो सतत् विकास उद्देश्यों के साथ उनके संरेखण को दरशाता है।
 - ॰ SGrBs जारी करने हेतु वित्तपोषित परियोजनाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चिति करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हरित मानकों एवं परमाणन परकरियाओं का पालन करना आवशयक है।
- वर्गीकरण:
 - SGrB को वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) के तहत वर्गीकृत किया गया है, जो वित्तीय संस्थानों के लिये RBI द्वारा निर्धारित तरलता दर है।
 - वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों को ऋण देने से पहले SLR अपने पास रखना चाहिये, जिससे अन्य उद्देश्यों हेतु धन की उपलब्धता प्रभावित होती है।
- गरीनियमः
 - चूँकि SGB आमतौर पर पारंपरिक G-सेक की तुलना में न्यूनतम ब्याज दरें प्रदान करते हैं,SGrB और G-सेक के बीच ब्याज दरों के अंतर को गरीनियम कहा जाता है।

• वैश्विक स्तर पर केंद्रीय बैंक और सरकारें हरित भविष्य में परिवर्तन का समर्थन करने के लिये ग्रीनियम को अपनाने को प्रोत्साहित करती हैं।

सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड फ्रेमवर्क:

- ॰ वित्त मंत्रालयं ने वर्ष 2022 में भारत का पहला SGrB फ्रेमवर्क जारी किया, जिसमें इस प्रकार की परियोजनाओं का विवरण दिया गया, जिनहें इस वरग के बॉणड के माध्यम से धन परापत होगा।
- वित्तपोषित परियोजनाएँ:
 - फंड को नौ हरित परियोजना श्रेणियों की ओर निर्देशित किया जाएगा: जिस्में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, स्वच्छ परिवहन, जलवायु अनुकूलन, सतत् जल प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण, सतत् भूमि उपयोग, हरित भवन और जैववविधिता संरक्षण शामिल हैं।

• बहिष्कृत परियोजनाएँ:

- जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और प्रत्यक्ष अपशिष्ट दहन से जुड़ी परियोजनाएँ। इसके अतिरिक्ति शराब, हथियार, तंबाकु, जुआ या पाम ऑयल उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं को भी पृथक रखा गया है।
- इसके अतरिकित संरक्षित क्षेत्रों से **बायोमास का उपयोग करने वाली नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाएँ, लैंडफिल परियोजनाएँ और **25 मेगावाट से बड़े <u>जलविद्युत संयंतर</u> पात्र नहीं** हैं।
- भारत सरकार ने विश्वसनीयता बढ़ाने के लिये नॉर्वे स्थिति वैलिंडिटर सिसेरों से मान्यता की मांग की है। सिसेरों ने अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार संघ (ICMA) द्वारा निर्धारित वैश्विक हरित मानकों के साथ संरेखण दर्शाते हुए "सुशासन" के स्कोर के साथ भारतीय ढाँचे का "हरित माध्यम" के रूप में मूल्यांकन किया।

SGrB की विशेषताएँ:

- ॰ **इन्हें समान मूल्य नीलामी** (एक सार्वजनिक विक्रय जहाँ एक ही कीमत पर समान वस्तुओं की एक निश्चित संख्या बेची जाती है) के माध्यम से जारी किया जाता है।
- ॰ <u>पनरखरीद लेन-देन (रेपो)</u> के लिये पात्र।
- ॰ SLR प्रयोजनों के लिये पात्र निवश के रूप में गनिती।
- द्वितीयक बाज़ार में व्यापार के लिये पात्र ।

प्रबंधन:

- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड आय को भारत के समेकित कोष में जमा किया जाएगा और वितृत मंत्रालय के सार्वजनिक ऋण प्रबंधन सेल द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
- ॰ हरति बॉण्ड के आवंटन और उपयोग का ऑडटि <u>भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)</u> द्वारा किया जाएगा।

• लाभ:

- भारतीय हरति बॉण्ड न केवल स्थिरता लक्ष्यों का समर्थन करते हैं बल्कि निविशकों को आकर्षित करके और केंद्रीय बैंक के भीतर निधि बढ़ाकर भारतीय मुद्रा को भी मज़बूत करते हैं।
- सामाजिक रूप से ज़िम्मेदार निवश की बढ़ती मांग और हरित बॉण्ड की सीमित आपूर्त उनकी कीमत और उपज बढ़ा सकती है।

हरति बॉण्ड में FII का नविश भारत के हरति संक्रमण को कैसे बढ़ावा देता है?

- भारत की हरति परियोजनाओं में नविश करने वाले FII देश के महत्त्वाकांक्ष<u>ी 2070 शृद्ध शून्य लकष्यों</u> को वित्तपोषित करने के लिये पूंजी पूल का विस्तार करते हैं, जिसका लक्ष्य भारत की 50% ऊर्जा गैर-जीवाशम ईधन स्रोतों से प्राप्त करना और देश की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना, जैसा कि ग्लासगो 2021 में संयुक्त राषटर जलवाय परिवरतन सममेलन (COP 26) में वादा किया गया था।
- FII फंडिंग का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करते हैं, घरेलू उधारदाताओं पर दबाव कम करते हैं और अन्य उपयोगों के लिये पूंजी मुक्त करते हैं।
- विदेशी निवशकों के हालिया समावेश ने भारत के SGrB के लिये संभावित निवेशकों के पूल का विस्तार किया है, जिससे संभावित हरित परियोजनाओं के लिये अधिक निधि प्राप्त हो रही है, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्बन फुटप्रिट को कम करना है तथा भारत के सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान देना है।
 - ॰ सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2024 में SGrB के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाना है और वित्त वर्ष 2025 के पहले छह महीनों में 12,000 करोड़ रुपए उधार लेने <mark>की योजना है</mark>।
- विदेशी निवशक हरति प्रौद्योगिकियों और परियोजना प्रबंधन में बहुमूल्य ज्ञान एवं अनुभव प्रदान कर भारतीय हरति बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को लाभ पहुँचा सकता हैं।

SGrB के संबंध में भारत की क्या चुनौतयाँ हैं?

हरति वर्गीकरण का अभाव:

- किसी निवश की पर्यावरणीय साख का आकलन करने के लिये हरित वर्गीकरण या मानकीकृत पद्धिति का अभाव एक चुनौती उत्पन्न करता
 है।
 - स्पष्ट मानदंडों के बिना ग्रीनवाँशि का जोखिम होता है, जहाँ परियोजनाएँ फंडिंग सुरक्षित करने के लिये पर्यावरण के अनुकूल होने का झूठा दावा करती हैं।

रूपरेखा का कार्यान्वयन:

- ॰ वितत मंतरालय ने भारत की पहली SGrB रुपरेखा जारी की, इसका कारयानवयन और प्रवरतन संकटपुरण बना हुआ है।
- ॰ यह सुनश्चिति करना कि वित्तिपोषित परियोजनाएँ परिभाषिति मानदंडों के अनुरूप हों और पर्यावरणीय स्थरिता में योगदान दें, इसके लिये मज़बूत निगरानी एवं मूल्यांकन तंत्र की आवश्यकता होती है।
- परियोजना चयन और प्रभाव:

- ॰ विश्वसनीय ऑडिट ट्रेल्स और उच्च प्रभाव वाली नई हरित परियोजनाओं की पहचान करना SGrB आय की इष्टतम प्राप्ति के लिये महत्त्वपूर्ण है।
 - सीमित निजी पूंजी वाली परियोजनाएँ, जैसे कि वितिरित नवीकरणीय ऊर्जा और MSME के लिये स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण हेतु
 पर्यापत धन आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड सकता है।
- उपयुक्त परियोजनाओं की उपलब्धता:
 - पात्र हरित परियोजनाओं की पाइपलाइन को सुरक्षित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से अतिटीय पवन ग्रिड पैमाने पर सौर <u>ऊर्जा उत्पादन</u> और इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles- EVs) जैसे क्षेत्रों में।
 - सरकार को नविश के अवसरों के नरिंतर प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिये ऐसी परियोजनाओं के विकास को सक्रिय रूप से **परोतसाहति** करने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ग्रीन बॉण्ड जारी करने में **पारदर्शता बढ़ाना** और मौजूदा चुनौतयिों का समाधान करना।
 - ॰ हरति परियोजनाओं में नविश के लाभों को बढ़ावा देने के लिये विशेष जागरुकता कार्यकरम लागु करना।
- निजी निवशकों के लिये अनुकूल वातावरण सुनिश्चित कर कानूनी, डिफॉल्ट, तरलता और अन्य जोखिमों को कम करना।
 - नविशकों का विश्वास बढ़ाने के लिये डिफॉल्टरों के संबंध में मज़बूत कानूनी ढाँचे को लागू करना ।
- घरेलू मांग को प्रोत्साहति करने के लिये **हरति पूंजी पूल** की स्थापना को प्राथमिकता देना।
- हरति परियोजनाओं को संस्थागत निवशकों के पोर्टफोलियों में एकीकृत करना, जिसमें संभावित रूप से भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI) जैसे भारतीय संस्थान शामिल हों।

प्रश्न. हरति परियोजनाओं में नविश को बढ़ावा देने और भारत के ग्रीन बॉण्ड बाज़ार के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये आवश्यक नीतिगत उपायों का आकलन कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारतीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल निम्नलिखिति में से किससे/किनसे प्रभावित होता है/होते हैं?

- 1. यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रज़िर्व की कार्रवाई
- 2. भारतीय रज़िर्व बैंक की कार्रवाई
- 3. मुदरासफीति एवं अल्पावधि बयाज दर

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिय:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

<u>????????</u>

प्रश्न: नवंबर 2021 में ग्लासगो में COP26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के वर्ल्ड लीडर्स समिट में शुरू की गई ग्रीन ग्रिड पहल के उद्देश्य की व्याख्या कीजिये। यह विचार पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में कब लाया गया था? (2021)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/fiis-to-invest-in-india-s-sovereign-green-bonds